Postal Regn No/ RYP DN/ 34/2017-19

शहर की

जनता से रिश्ता

छत्तीसगढ़ का पहला मिड-डे अखबार

हिन्दी दैनिक

जो दिखेगा वो छपेगा

www.jantaserishta.com jantaserishta@gmail.com » ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष: दशमी » ★ रायपुर, बुधवार 12 जून 2019 » वर्ष : 07 अंक : 43 » पृष्ठ - 12 » मूल्य - 2 रुपए

'एक व्यक्ति-एक पद' का सिद्धांत आड़े नहीं?

शाह बने रहेंगे भाजपाध्यक्ष!

नई दिल्ली (ए./नेट डेस्क/टीवी चैनल्स)। बीजेपी के शीर्ष सूत्रों के अनुसार लोकसभा से लेकर विधानसभा चुनावों में बीजेपी के लिए इलेक्शन विनिंग मशीन बने अमित शाह गृह मंत्री के साथ-साथ पार्टी अध्यक्ष भी बने रह सकते हैं। आगामी हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली के विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी अध्यक्ष की कुर्सी को लेकर पार्टी किसी तरह का रिस्क उठाने के मूड में नहीं है। अमित शाह के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठने के बाद से संगठन में कायम हुई हनक और नतीजों से कार्यकर्ताओं में पैदा हुए जोश को बीजेपी बनाए रखना चाहती है।

बीजेपी के विश्वस्त सूत्रों ने आज तक डॉट इन से कहा कि आज के दौर में अमित शाह में वो क्षमता है कि वे अति व्यस्त गृह मंत्रालय के साथ 11 करोड़ सदस्यों वाली देश की सबसे बड़ी पार्टी को एक साथ चला सकते हैं। नया अध्यक्ष कौन होगा? राष्ट्रीय स्तर के एक कद्दावर पदाधिकारी पहले इस सवाल पर हल्की मुस्कान बिखेरते हैं और फिर कहते हैं- चर्चाएं जो भी हों, जहां तक मुझे सूचना है कि अध्यक्ष जी अभी पद पर बने रहेंगे। यह सब उन पर(अमित शाह) ही निर्भर है।

क्या नियम आड़े आएंगे? : बीजेपी में एक व्यक्ति-एक पद सिद्धांत लागू होने की बात कही जाती है। मतलब कि संगठन में रहते सरकार में भूमिका नहीं निभा सकते। मगर पार्टी के सितंबर, 2012 में संशोधन के बाद तैयार हुए नए संविधान में इसका कोई लिखित में जिक्र नहीं मिलता। बीजेपी की वेबसाइट पर मौजूद 46 पेज के संविधान में यूं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर स्थानीय पदाधिकारियों के चुनाव तक के नियम-कायदे दर्ज हैं। मगर इसमें अध्यक्ष पद के लिए कहीं एक व्यक्ति-एक पद सिद्धांत की शर्तें नहीं दिखतीं। बीजेपी की वेबसाइट पर मौजूद यह संविधान, सितंबर 2012 में नए सिरे से तैयार हुआ था। बीजेपी की मई 2012 में मुंबई में हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में अध्यक्ष को तीन-तीन साल का दो कार्यकाल देने का प्रस्ताव पास हुआ था। जिसे सितंबर 2012 में सूरजकुंड की बैठक में मंजूरी मिली थी। पहले सिर्फ तीन साल के एक कार्यकाल तक ही कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष रह सकता था। हालांकि 2014 में जब राजनाथ सिंह मोदी कैबिनेट में शामिल हुए तो उन्होंने अध्यक्ष पद छोड़ दिया था। सूत्र बता रहे हैं कि यह केस टू केस मामला हो सकता है। जरूरी नहीं कि जो पहले होता आया हो, वही इस बार अमित शाह के मामले में भी हो। बीजेपी की दिल्ली प्रदेश इकाई के एक पदाधिकारी आजतक से कहते हैं- जहां तक मुझे ख्याल है बीजेपी के मूल संविधान में तो एक व्यक्ति-एक पद सिद्धांत जैसी बात कहीं गई थी, मगर हो सकता है कि 2012 में तीन साल के एक ही कार्यकाल की तरह इस नियम को भी हटा दिया गया हो। सूत्रों का यह भी नजीर देते हैं कि 2014 में पार्टी का कोषाध्यक्ष होने के बावजूद पीयूष गोयल मंत्री बने। यह दीगर है कि बाद में उनके कोषाध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की खबरें आईं। वहीं पार्टी की वेबसाइट से कोषाध्यक्ष के रूप में उनका नाम हट गया। फिलहाल बीजेपी का आधिकारिक रूप से कोषाध्यक्ष कौन है, इसको लेकर संशय कायम है।

2022 तक अध्यक्ष रह सकते हैं शाह : मोदी कैबिनेट में शामिल होने पर राजनाथ सिंह के 2014 में अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद उनका बचा दो साल का कार्यकाल अमित शाह ने पूरा किया था। जिसके बाद 2016 में पहली बार वह तीन साल के पूर्ण कार्यकाल के लिए अध्यक्ष चुने गए। जनवरी 2019 में तीन साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद 11-12 जनवरी को हुई राष्ट्रीय परिषद की बैठक में शाह को आम चुनाव तक सेवा विस्तार दिया गया। बीजेपी के मौजूदा संविधान के मुताबिक कोई व्यक्ति तीन-तीन साल के दो पूर्ण कार्यकाल तक अध्यक्ष पद पर रह सकता है। ऐसे में अमित शाह बिना संविधान संशोधन हुए 2022 तक अध्यक्ष रह सकते हैं।

शाह का विकल्प नहीं : पार्टी के एक नेता कहते हैं कि भले ही बीजेपी काडर बेस पार्टी है, नेताओं की कमी नहीं हैं। मगर संगठन चलाने के मामले में अमित शाह का कोई विकल्प नहीं है। उनकी पार्टी की पूरी कार्यप्रणाली बदलकर रख दी।

महाराष्ट्र: बीजेपी-शिवसेना के बीच गठबंधन लगभग तय, विधानसभा चुनाव में ढाई-ढाई साल का फॉर्मूला!

मुंबई। महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार को शिवसेना कितना भी कोसे, लेकिन लोकसभा चुनाव दोनों मिलकर लड़ेंगे। यह बात लगभग तय हो गई है। हालांकि विधानसभा चुनावों में गठबंधन का पेच मुख्यमंत्री पद को लेकर फंसा हुआ है। बीजेपी की तरफ से बताया जा रहा है कि फिफ्टी-फिफ्टी सीटों के फॉर्मूले पर चुनाव लड़ने के लिए दोनों दलों में सहमति बन गई है। मुख्यमंत्री पद को लेकर बीजेपी ने शिवसेना के सामने ढाई-ढाई साल का फॉर्मूला रखा है। महाराष्ट्र में लोकसभा की कुल 48 सीटें हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 26 सीटों पर चुनाव लड़ा और 23 सीटों पर जीतकर आई, जबकि शिवसेना ने 22 सीटों पर चुनाव लड़कर 18 सीटों पर जीत दर्ज की। अब फिर लोकसभा चुनाव सिर पर हैं और शिवसेना अपने मुताबिक समझौता करना चाहती है। बैक डोर से दोनों दलों के बीच गठजोड़ के लिए दिल्ली से लेकर मुंबई तक कसरत की गई। नतीजे सामने हैं।

ढाई-ढाई साल का फॉर्मूला : माना जा रहा है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 25 और शिवसेना 23 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पालघर सीट छोड़ने के लिए बीजेपी अब तैयार है। लोकसभा के साथ-साथ विधानसभा चुनावों में भी सीटों का बंटवारा लगभग तय है। मुख्यमंत्री पद को लेकर मामला थोड़ा अटका है। शिवसेना का कहना है विधानसभा चुनाव में किसी की भी सीटें ज्यादा आएं, लेकिन मुख्यमंत्री शिवसेना का ही होगा। अब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अपनी सीट इतनी आसानी से शिवसेना को कैसे दे देंगे, फिर भी बीजेपी ने ढाई-ढाई साल का फॉर्मूला शिवसेना के सामने रखा है। दरअसल, शिवसेना की इस भूमिका को बीजेपी इस नजर से देख रही है कि उन्हें (शिवसेना को) अगली सरकार में मालदार मंत्री पद चाहिए, जैसे- पिछली आघाड़ी सरकार में एनसीपी ने कांग्रेस के साथ किया था। मुख्यमंत्री कांग्रेस का था और मलाईदार मंत्री पद एनसीपी के पास था।

मोदी कैबिनेट की आज पहली बैठक, होंगे अहम फैसले

नई दिल्ली (ए.)। मंत्रियों को जिम्मेदारियां सौंपे जाने के बाद केंद्रीय मंत्रिपरिषद की पहली बैठक बुधवार को होगी, जिसमें सरकार के लघु और दीर्घकालिक अजेंडे पर चर्चा की संभावना है। यह बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार के सभी सचिवों के साथ हुई बातचीत के अगले दिन होने जा रही है। इस बैठक के बाद केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी। सूत्रों ने बताया कि इस बैठक में पांच जुलाई को संसद में पेश किए जाने वाले केंद्रीय बजट की तैयारियों पर चर्चा संभावित है। इसके अलावा इस बैठक में कैबिनेट कुछ विधेयकों को भी मंजूरी दे सकती है जो पिछली सरकार के कार्यकाल में पास नहीं हो पाए थे। 16वीं लोकसभा के कार्यकाल में तीन तलाक विधेयक लोकसभा में मंजूर हो गया था लेकिन राज्यसभा में संख्याबल कम होने की वजह से यह पास नहीं हो पाया था। माना जा रहा है कि सरकार इस बिल को लेकर गंभीर है और दोबारा इसे संसद में पास कराने की पूरी कोशिश की जाएगी। केंद्रीय बजट प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई वाली नई राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के इरादे का पहला बयान होगा। इसमें सरकार की अगले पांच वर्षों की सोच का व्यापक खाका खींचे जाने की संभावना है। सचिवों के साथ हुई बैठक में मोदी ने उनसे कहा था कि योजना व रोडमैप बनाना और भारत को पांच महाशंख डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए फैसले लेना उनकी शीर्ष प्राथमिकता है। इस बैठक में मोदी के नए मंत्रिपरिषद के सभी मंत्री शामिल होंगे।

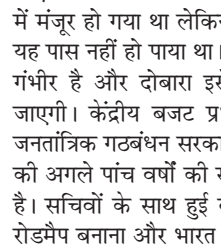

नृपेंद्र मिश्रा प्रधान सचिव, पीके मिश्रा अतिरिक्त प्रधान सचिव बने रहेंगे

नृपेंद्र मिश्रा और पी. के. मिश्रा को मंगलवार को फिर से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का क्रमशः प्रधान सचिव और अतिरिक्त प्रधान सचिव नियुक्त किया गया। दोनों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी दिया गया है। कार्मिक मंत्रालय के अनुसार, कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने 31 मई के प्रभाव से दोनों की नियुक्तियों को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि दोनों का कार्यकाल प्रधानमंत्री के कार्यकाल के साथ पूरा होगा।

राज्यसभा में थावरचंद गहलोत होंगे सदन के नेता, जेटली की लेंगे जगह

नई दिल्ली (ए.)। भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के वरिष्ठ नेता थावरचंद गहलोत राज्यसभा में सदन के नेता होंगे। गहलोत पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली की जगह लेंगे। जेटली ने पीएम नरेंद्र मोदी से स्वास्थ्य कारणों से मंत्रिमंडल में शामिल नहीं करने का आग्रह किया था। गहलोत पीएम नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल में सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्री हैं। गहलोत बीजेपी के प्रमुख दलित नेता हैं। 2014 में पीएम मोदी के पहले कार्यकाल में भी गहलोत को सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय की जिम्मेदारी ही मिली थी। गहलोत 1996 से 2009 के दौरान शाजापुर लोकसभा सीट से सांसद रहे। 2012 में थावर चंद गहलोत को राज्यसभा सदस्य चुना गया। 2018 में गहलोत को दोबारा राज्यसभा के लिए चुना गया। राज्यसभा सदस्य के तौर पर उनका कार्यकाल 2024 में खत्म होगा।

भाजपा के डॉ. वीरेंद्र कुमार होंगे लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर।

लापता विमान का मलबा दिखा...

नई दिल्ली। भारतीय वायुसेना के लापता एएन-32 विमान का मलबा आठ दिन बाद मिला। एएन-32 विमान का मलबा अरुणाचल प्रदेश के टाटो इलाके में लगभग 12,000 फुट की ऊंचाई पर मिला। सूत्रों की तरफ से शेयर किए गए तस्वीर में एएन-32 विमान का मलबा और झुलसे हुए पेड़ साफ नजर आ रहे हैं, जो इशारा करते हैं कि जब विमान गिरा होगा तो कितनी जबर्दस्त आग लगी होगी। बता दें कि बीते 3 जून को लापता हुए एएन-32 विमान ने 8 क्रू मेंबर और 5 यात्रियों के साथ उड़ान भरी थी। इस विमान को तलाशने के लिए इंडियन एयरफोर्स ने लगातार अभियान जारी कर रखा था।

हॉट न्यूज टुडे

प्लेन हाइजैक की अफवाह पर कारोबारी को उम्रकैद, 5 करोड़ फाइन

अहमदाबाद (ए.)। प्लेन हाईजैक की अफवाहें उड़ाने वालों के बारे में आपने कई बार सुना होगा, लेकिन ऐसा करना दक्षिण मुंबई के एक कारोबारी को बेहद भारी पड़ा है। देश में नए बने कड़े ऐंटी-हाइजैकिंग लॉ के तहत कारोबारी बिरजू सल्ला को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है और 5 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगा है। मंगलवार को नैशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने बिरजू सल्ला को इस नए कानून के तहत पहली सजा सुनाई। ऐंटी हाइजैकिंग ऐक्ट, 2016 के तहत बिरजू सल्ला को यह सजा सुनाई गई। बिरजू ने अक्टूबर, 2017 में मुंबई-दिल्ली के बीच जेट एयरवेज की फ्लाइट के शौचालय में हाइजैक की धमकी वाला लेटर डाल दिया था। इस लेटर में कहा गया था कि हाइजैकर्स प्लेन में ही हैं और विमान को सीधे पीओके ले जाया जाए। यही नहीं लेटर में कहा गया था कि यदि विमान को कहीं और उतारने की कोशिश की गई तो लोगों को मार दिया जाएगा। प्लेन के कार्गो एरिया में बम प्लांट होने की धमकी दी गई थी।

बीजेपी ने दिया डेप्युटी स्पीकर पद का ऑफर जगन की पार्टी को?

विजयवाड़ा (ए.)। बीजेपी ने आंध्र प्रदेश के सीएम वाईएसआर जगन मोहन की पार्टी वाईएसआर कांग्रेस को डेप्युटी स्पीकर का पद ऑफर किया है। वाईएसआर कांग्रेस के 22 सांसद हैं। बीजेपी के प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा राव ने मंगलवार को जगन मोहन रेड्डी से मुलाकात कर लोकसभा में डेप्युटी स्पीकर का पद दिया। सूत्रों के अनुसार, जीवीएल ने पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह की ओर से यह ऑफर जगन को दिया। सूत्रों का कहना है कि जगन ने फिलहाल इस पर कोई फैसला नहीं लिया है और ऑफर पर सोचने के लिए वक्त मांगा है। इस ऑफर को स्वीकारने के अपने राजनीतिक संदेश भी हो सकते हैं। जगन की पार्टी के लिए प्रदेश के अल्पसंख्यक मुस्लिम और ईसाई समुदाय के लोगों ने बड़ी संख्या में वोट किया है। सूत्रों का कहना है कि वोट बैंक को देखते हुए जगन इस ऑफर को स्वीकार करने से पहले पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से चर्चा करेंगे।

चक्रवाती तूफान 'वायु' आज-कल में टकराएगा गुजरात तट से, हाईअलर्ट

नई दिल्ली (ए.)। ओडिशा में पिछले महीने फैनी तूफान से मची तबाही के बाद अब पश्चिम में गुजरात पर ऐसे ही एक भयानक तूफान का खतरा मंडरा रहा है। दरअसल, अरब सागर में पैदा हुआ चक्रवाती तूफान 'वायु' महाराष्ट्र से उत्तर में गुजरात की ओर बढ़ रहा है। मौसम विभाग द्वारा मंगलवार को जारी बुलेटिन के अनुसार 'वायु' के 13 जून को गुजरात के तटीय इलाकों पोरबंदर और कच्छ क्षेत्र में पहुंचने की संभावना है। विभाग ने अगले 12 घंटों में चक्रवाती तूफान के और अधिक गंभीर रूप धारण करने की संभावना जताई है। उधर, गुजरात के अधिकारी ओडिशा में आए फोनी तूफान के समय अपनाई गई तकनीक के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक कर तैयारियों का जायजा लिया है। IMD के मुताबिक उत्तर की ओर बढ़ता 'वायु' 13 जून को सुबह गुजरात के तटीय इलाकों में पोरबंदर से महुवा, वेरावल और दीव क्षेत्र को प्रभावित करेगा। इसकी गति 110 से 130 किमी प्रति घंटा तक हो सकती है। उत्तरी महाराष्ट्र के तटों पर 70 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं।

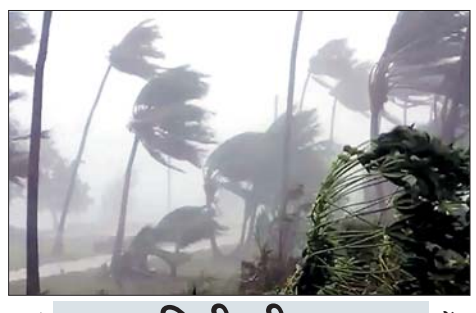

165 किमी की रफ्तार, स्कूल-कॉलेजों में छुट्टी

10 जिलों के स्कूल-कॉलेजों में 2 दिन की छुट्टी : गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने पूरे राज्य में 13 से 15 जून तक तीन दिवसीय शाला प्रवेशोत्सव कार्यक्रम रद्द कर दिया है। उन्होंने वायु चक्रवात से संभावित रूप से प्रभावित होने वाले 10 जिलों में 13 और 14 जून को स्कूल और कॉलेजों में 2 दिन की छुट्टी घोषित कर दी है।

गुजरात सरकार का हाई अलर्ट, NDRF तैनात : मौसम विभाग ने इसके मद्देनजर सौराष्ट्र और कच्छ के तटीय इलाकों में 13 और 14 जून को भारी बारिश होने और 110 किमी प्रति घंटे की गति से तूफानी हवाएं चलने की चेतावनी जारी की है। इसे देखते हुए गुजरात सरकार ने भी 'हाई अलर्ट' जारी करते हुए सौराष्ट्र और कच्छ इलाकों में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के जवानों को तैनात किया है। सरकार ने तटीय क्षेत्रों में मछुआरों को अगले कुछ दिनों तक समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी है। साथ ही बंदरगाहों को खतरे के संकेत और सूचना जारी करने को कहा गया है।

चार राज्यों के राज्यपालों ने शाह से की मुलाकात

नई दिल्ली (ए.)। राजस्थान समेत चार राज्यों के राज्यपालों ने मंगलवार को गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और अपने-अपने राज्यों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। अधिकारियों ने यह जानकारी दी जिन राज्यपालों ने शाह से मुलाकात की उनमें राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह, गुजरात के राज्यपाल ओम प्रकाश कोहली, कर्नाटक के राज्यपाल वजुभाई वाला और उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य शामिल हैं। राज्यपालों ने अलग-अलग शाह से मुलाकात की और गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने इन बैठकों को नए गृह मंत्री के साथ शिष्टाचार भेंट बताया। बतौर गृह मंत्री, शाह ने एक जून को कार्यभार संभाला था। अधिकारी ने बताया कि गृह मंत्री ने राज्यपालों के साथ उनके राज्यों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की।

महत्वपूर्ण खबरें

पांच वर्षों में 5 करोड़ अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को दी जाएगी स्कॉलरशिप

नई दिल्ली (ए.)। मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं को शिक्षित कर आगे बढ़ाने की दिशा में बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने मंगलवार को ऐलान किया कि अल्पसंख्यक समाज के सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण के लिए अगले पांच वर्षों में पांच करोड़ विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जाएगी और इनमें आधी संख्या में लड़कियां होंगी।

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की अधीनस्थ संस्था मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान की 65वीं आमसभा की बैठक के बाद नकवी ने पत्रकारों से कहा, 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली इंसाफ, ईमान और इकबाल की सरकार ने विकास की सेहत को सांप्रदायिकता एवं तुष्टीकरण की बीमारी से मुक्ति दिलाकर सेहतमंद, समावेशी सशक्तिकरण का माहौल तैयार किया है।'

अगले महीने से मदरसा शिक्षकों को ट्रेनिंग : उन्होंने कहा, 'अल्पसंख्यक वर्ग की स्कूल ड्रॉपआउट लड़कियों को देश के प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों से ब्रिज कोर्स कराकर उन्हें शिक्षा और रोजगार से जोड़ा जाएगा। देशभर के मदरसों में मुख्यधारा की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए मदरसा शिक्षकों को विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों से प्रशिक्षण दिलाया जाएगा ताकि वे मदरसों में मुख्यधारा की शिक्षा- हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, कंप्यूटर आदि दे सकें। यह काम अगले महीने से शुरू कर दिया जाएगा।'

इसरो के चंद्रयान-2 मिशन की लॉन्चिंग की तैयारी, जुलाई में होगा रवाना

बेंगलुरु (ए.)। इसरो अपने महत्वाकांक्षी चंद्रयान-2 मिशन की टेस्टिंग के आखिरी राउंड में है। तमिलनाडु के महेंद्रगिरी और बेंगलुरु के ब्यालालू में फाइनल टेस्ट चल रहा है। इसरो की तैयारी 9 जुलाई से लॉन्चिंग शुरू करने की है। इसरो के मौजूदा शेड्यूल के मुताबिक स्पेसक्राफ्ट 19 जून को बेंगलुरु से रवाना होगा और 20 या 21 जून तक श्रीहरिकोटा के लॉन्चपैड पर पहुंचेगा। थ्री डी मैपिंग से लेकर वॉटर मॉलिक्यूल्स तक और मिनरल्स की चेकिंग से उस जगह पर लैंडिंग तक जहां आज तक कोई नहीं पहुंचा है। इसरो ने चांद पर जाने की बड़ी तैयारी कर रखी है। इसरो के इस महत्वाकांक्षी मिशन की कई चुनौतियां भी हैं।

एक्युरेसी की मुश्किल

धरती से चांद की दूरी 3,844 किलोमीटर है। ट्राजेक्टरी एक्युरेसी मुख्य चीज है। यह चांद की ग्रेवेटी से प्रभावित है। इसके अलावा चांद पर अन्य खगोलविद संस्थाओं की मौजूदगी और सोलर रैडिएशन का भी इस पर प्रभाव पड़ने वाला है।

डीप-स्पेस कॉम्युनिकेशन

कॉम्युनिकेशन में देरी भी एक बड़ी समस्या होगी। कोई भी संदेश भेजने पर उसके पहुंचने में कुछ मिनट लगेंगे। सिग्नल्स वीक हो सकते हैं। इसके अलावा बैकग्राउंड का शोर भी संवाद को प्रभावित करेगा।

ताजा खबर

- तमिलनाडु: कोयंबटूर में 7 जगहों पर एनआईए की छापेमारी
- गंगा दशहरा आज, श्रद्धालुओं ने गंगा घाटों पर लगाई आस्था की डुबकी
- बंगाल: हावड़ा में बनेगा राम मंदिर, 15 सितंबर को योगी करेंगे शिलान्यास

ब्रेकिंग न्यूज

- आज दोपहर कांग्रेस कोर ग्रुप की बैठक, तीन राज्यों के चुनावों को लेकर होगी चर्चा
- ISI ने जम्मू-कश्मीर में बनाया नया अलगाववादी गुट: सूत्र